

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि
 वादी/रूपी. संख्या एक ने अपीलेंट के विरुद्ध एक वाद
 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान करलकरी
 अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय
 का प्रेष किया कि याम रजोद में खसरा नं. 1144 रकबा
 10.15 बीघा, खसरा नं. 929 रकबा 10.19 बीघा, खसरा नं.
 1288/1 रकबा 05.07 बीघा खसरा नं. 1054/4 रकबा 03.18
 बीघा कुल रकबा 30.09 बीघा अंश पर प्रतिवादी भोमाराम
 पुत्र श्री आइंदनराम जाट विवासी- रजोद की खानेदारी
 अंश है। उक्त अंश में से वादी सुरेन्द्र पुत्र भोमाराम
 विवासी- रजोद जस्ये वगी भाता श्रीमती कर्कड़ी पत्नी श्री
 भोमाराम ने प्रतिवादी संख्या एक के साथ 1/2-1/2 हिस्सा
 पुरेवणी अंश में खानेदारी अधिकार धारित करवाना चाहता
 है। प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध स्याई विषयाज्ञा जारी
 की जावे कि वादीवपु के काल में कोई दखलदानी नहीं
 करे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद नं रजिस्टर
 किया जाकर प्रतिवादी/अपीलार्थी को जसिय जारी किया
 गये। अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रेष किया गया। स्याही
 वादी ने पीडब्ल्यू-1 सुरेन्द्र जसिये भाता कर्कड़ी के खोल
 लेखण्ड किया गये, तदनुसार सक्षय वादी वद कर पकावली
 साक्ष्य प्रतिवादी हेतु जसिय की गयी। साक्ष्य प्रतिवादी के
 दायरे पकावली लोक अदालत कक्ष रजोद में प्रस्तुत हुई



को प्रेष की गयी है।

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 जुलाई 2018

राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय
जोधपुर

[Handwritten signature]

उपस्थित नहीं था, परन्तु किशोर शर्मा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी लोक अदालत के समक्ष दौरे पर नहीं की सहमति के आधार पर परीक्षा के लिए जाने योग्य है। राजस्थान लोक अदालत में राजीनामा के प्रकरण करण अधीनस्थ न्यायालय को लिखित अपारत किसे जाने प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। इस परिणत कर डिक्री पत्र जारी कर दिया गया एवं न ही बिना कोई वकस सूत्र, दिनांक 04.05.2018 को लिखित स्तर की प्रभावशी को बिना कोई साक्ष्य प्रतिवादी वद किसे, श्री, परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी को वाक्य लिखित सूत्रवाड हेतु लिखत की जाती राजीनामा नहीं होने की स्थिति में प्रभावशी पुनः न्यायालय 2018 को रखा गया था, वहीं पर दौरे पर प्रवेश के समय हेतु राजस्थान लोक अदालत केम रडोट हेतु दिनांक 04.05. प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु विचारणीय श्री, जिसे राजीनामा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रभावशी के सिद्धांत के विपरीत होने से अपारत किसे जाने योग्य परिणत लिखित एवं डिक्री दिनांक 04.05.2018 याकृतिक न्याय को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकस सूत्र जारी। अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय ने तयारी



बाई।

कर लिया गया, जिसके विरुद्ध आगे अपील प्रस्तुत की डिक्री दिनांक 04 मई 2018 जारी कर वादी का वाद स्वीकार नहीं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं

राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय
जोधपुर

[Handwritten signature]

न्यायालय ने अटिच पर लिफाया पारित कर आरी कांर्णी
 आल कांरि की है, इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय
 का लिफाया एवं डिक्ली दिनांक 04.05.2018 अपारत किसे जाने
 योज्य है। लिख का सारभूत सिद्धांत है कि जब तक कोई
 व्यक्ति जीवित होता है, तब तक उसके वारिसान् को उसके
 एक हिस्से की जमीन में कोई बंटवाडा नहीं हो सकता है,
 परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थों के जीवित
 होने के बावजूद भी अधीनस्थों की आर्भिक में अपाथी संख्या
 एक को खातेदार घोषित कर आरी आल कांरि की है।
 पडव्या-1 साक्षी श्रीमती कर्कुडी ने अपनी लिख में यह
 स्वीकार किया कि वह और उसका पुत्र वर्तमान में पीहर में
 करीब 8-9 साल से निवास कर रहे हैं, इस कारण साक्ष्य में
 यह भली भांति साबित है कि उक्त आरानी पर वादी का
 किसी प्रकार से कोई कब्जा कायम नहीं था, परन्तु फिर भी
 अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त साक्ष्य पर विश्वास करते हुए
 अधीनस्थों को डिक्ली जारी कर दी। अधीनस्थों ने
 डिक्ली जारी किया कि अधीन अधीनस्थ स्वीकार करमायी जाने
 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अधीनस्थों लिफाया
 एवं डिक्ली दिनांक 04 मई 2018 को अपारत किया जावे।
 नवाब में विद्वान अधीनस्थों के अपीलाटिस के
 अधीनस्थों के कथनों का विरोध करते हुए लिखते कि
 विवादास्पद आर्भिक पुरवानी आर्भिक होने से वादी/रिपॉन्डेंट का कांर्णल



पुस्तक अर्पित प्रमाणिका
जोधपुर

जन्म से 1/2 हिस्सा विहित है। अर्धीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं वादी की साक्ष्य के आधार पर विधिप्रमाणित किया गया है। अतः अपील के द्वारा पुनर्विलोकन की याचिका खारिज करमाया जावे।

विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अर्गुमन्त विधिप्रमाणित किया जाने का आदेश किया।

उपरोक्त प्रकरण के अधिवक्ताओं की उपरोक्त बहस पर विचारपूर्वक मजल किया गया एवं पत्रावलिओं पर उपलब्ध अभिलेख का आधुनिक अद्यतन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक विद्वान् न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी उपस्थित होने पर दिनांक 30.10.2015 को तनकीयात कायम की गई तथा पत्रावली वादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर प्रतिवादीवण की साक्ष्य में विचारार्थीन थी। अर्धीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये विना दिनांक 04 अक्टूबर 2018 को पत्रावली न्याय आणके द्वारा 2018 केम कोर्ट रजिस्ट्रार में रखकर अर्धीनस्थ न्यायालय विधिप्रमाणित किया जाना पया जाता है। वादी द्वारा अपने वाद में बटवाई की इस्तदुआ चाही गई थी। अर्धीनस्थ न्यायालय द्वारा बटवाई के अर्गुमन्त के बावजूद भी प्राथमिक इसकी जारी नहीं की गई तथा प्रकरण में तनकीयात विद्वान् किये विना अर्धीनस्थ न्यायालय विधिप्रमाणित किया जाना पया है। इन परिस्थितियों में अर्धीनस्थ न्यायालय विधिप्रमाणित अदालत द्वारा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पया जाता है।

उपरोक्त विद्वान् एवं विधिप्रमाण के आधार पर अपील अर्धीनस्थ न्यायालय सहायक



राजस्थान
 राजस्थान अधिकांश न्यायाधीश
 राजस्थान अधिकांश न्यायाधीश
 राजस्थान अधिकांश न्यायाधीश

20/11/2018

दिनांक 04 मई 2018 राजस्थान वार्द संख्या 213/2010 सूरेंद्र बलाम

कलक्टर एवं उपायुक्त अधिकांश न्यायाधीश द्वारा दिनांक एवं दिनांक
 दिनांक 04 मई 2018 राजस्थान वार्द संख्या 213/2010 सूरेंद्र बलाम
 श्रीमती गौतम को अपील किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय
 को इस निर्देश के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है कि वह मामले में
 प्रतिवादी/अपीलांत की साक्ष्य ली जाकर विहित न्यायिक प्रक्रिया का
 पालन करते हुए उभय पक्ष को समर्थित सुनवाई का अवसर प्रदान
 करे।

